

# GENERAL STUDIES (Module - 4)

निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)-M-GS14

अधिकतम अंक: 250  
Maximum Marks: 250

Name: Firoj Alam

Mobile Number: \_\_\_\_\_

Medium (English/Hindi): HINDI

Reg. Number: Awake-19/F005

Center & Date: 05/08/19

UPSC Roll No. (If allotted): 0833129

## प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:  
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

## QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

**Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:**

**There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.**

**All the questions are compulsory.**

**The number of marks carried by a question is indicated against it.**

**Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.**

**Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.**

**Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.**

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)  
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)  
Reviewer (Signature)



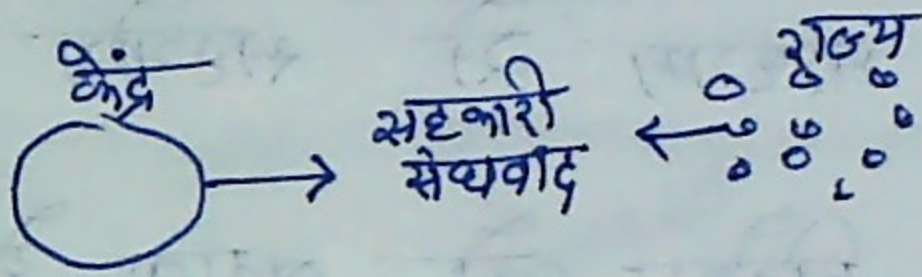
1. भारत में सहकारी संघवाद के संबंध में कौन-से संवैधानिक प्रावधान हैं? साथ ही प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग द्वारा हाल ही में किये गए कुछ उपायों पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

What are the Constitutional provisions regarding cooperative federalism in India? Also discuss some of the recent measures taken by NITI Aayog to foster competitive federalism. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य  
साथ में मिलकर कार्य करते हैं।



संवैधानिक प्रावधान

- ① 7वीं अनुसूची - इस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के स्पष्ट क्षेत्र का विभाजन किया गया है।
- ② अनु. 275 & 278 → केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती।
- ③ अनु. 280 → वित्त आयोग केंद्र-राज्यों के मध्य वित्तीय बंटवारे की सिफारिश करेगा।



नीति आयोग ने 17 जन 2015 के बाद  
सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए  
निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

- ① SDG का मूल्यांकन राज्यों के सहयोग  
से किया गया।
- ② शिक्षा मूल्यांकन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी  
मूल्यांकनों के माध्यम से सहयोग।
- ③ राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने  
का प्रयास किया गया।

### समाप्त

- ① CBI, CVC तथा Art-356 से सम्बन्धी  
मुद्दों का समाधान करने का भी  
प्रयास करना चाहिए।
- राजनीतिक - आर्थिक संघर्ष अंधीय  
व्यवस्था पर ही टिकी है मत इसे  
बदलने का प्रयास करना चाहिए।



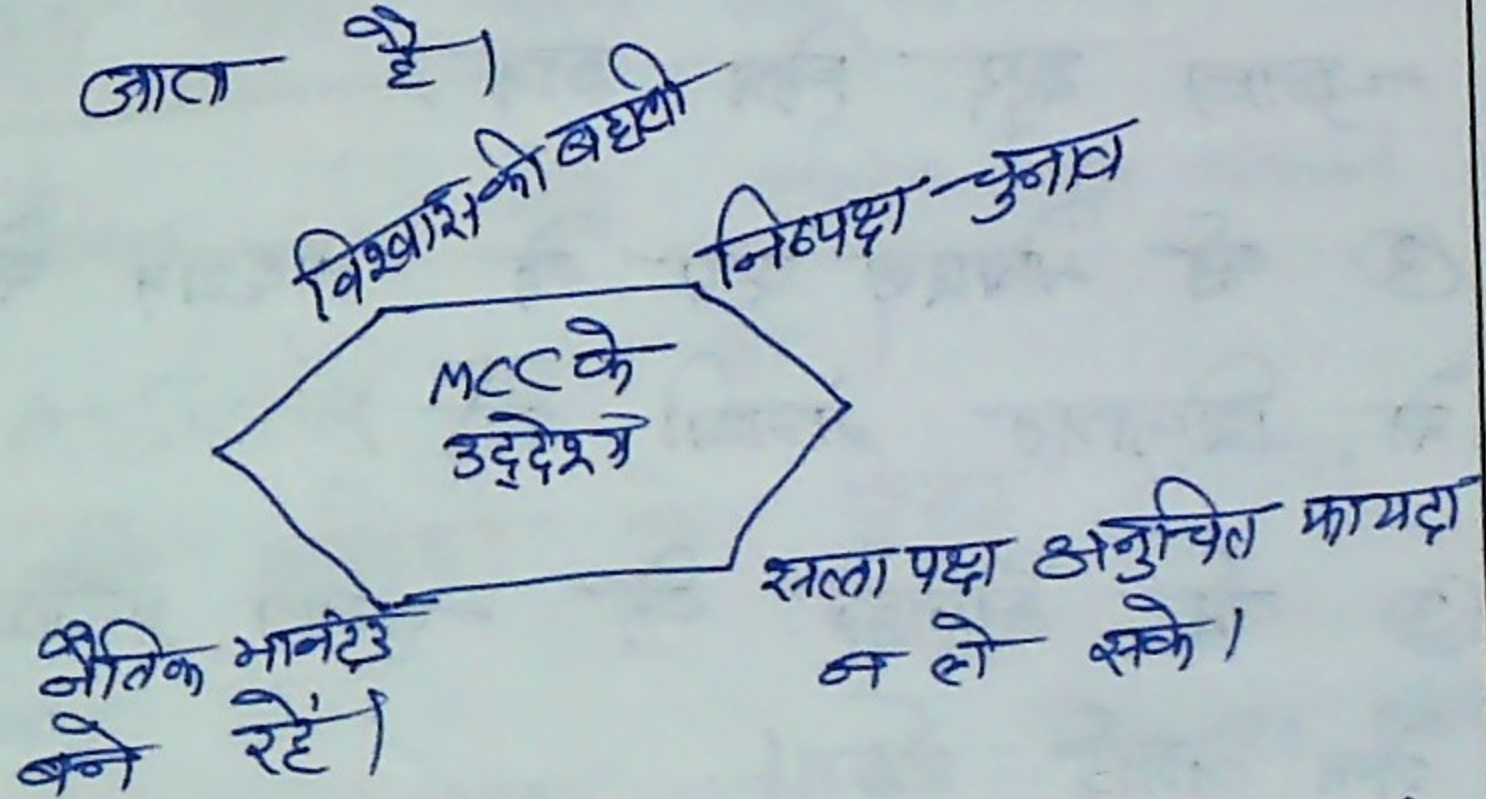
2. सोशल मीडिया के युग में आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) का प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्पष्ट कीजिये। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किये गए कुछ उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस  
हार्शिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

Enforcement of Model Code of Conduct (MCC) has become challenging in the era of social media. Elucidate. Also mention some of the measures taken by the Election Commission of India in this regard. (150 words) 10

आदर्श आचार संहिता (MCC) को  
निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाने  
के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कार्य  
किया जाता है।



सोशल मीडिया के युग में MCC का प्रवर्तन  
चुनौतीपूर्ण क्यों?

- ① सूचनाओं को शुरुआत (उद्भव) का पता नहीं लगा पाता।
- ② सूचनाओं का प्रसारण तेजी से होता है।



- (3) फ्रेंच - मुद्रा बढ़ती जा रही है।  
 (4) डेटा स्थानीयकरण का अभाव।

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।

(Candidate must not  
 write on this margin)

अनु० 324 व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम  
 1951 के अनुसार चुनाव आयोग ने  
 निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

- (1) तमिलनाडु के जल्लोर संसदीय क्षेत्र का  
 चुनाव रद्द किया गया।
- (2) कई भौतिक रूप के माध्यम से जनता  
 से शिकायतें संग्रहीत हुईं।
- (3) कई निर्वाचनों के चुनाव प्रचार पर  
 रोक लगाई गई।

### सुझाव

- (1) MCC को वैधानिक आधार प्रदान  
 करना चाहिए।
- (2) जनता को अधिक आवाकण करना  
 चाहिए।

**निष्कर्ष** स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु MCC  
 को लागू करवाना आवश्यक है।



3. किन परिस्थितियों में एक विधायक को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है? क्या आप सहमत हैं कि इसके लाभप्रद परिणाम के अपेक्षाकृत दुष्प्रभाव अधिक हैं? (150 शब्द) 10

What are the circumstances under which a legislator can be disqualified under anti-defection law? Do you agree that it has caused more harm than good? (150 words) 10

दम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

52वें संशोधन अधिनियम 1985

के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल-बदल के प्रावधान को जोड़ा गया।

अयोग्य घोषित करने हेतु प्रावधान

- ① बिना पार्टी को सूचित किए मतदान से अनुपस्थित रहना है।
  - ② पार्टी आदेशों के विरुद्ध मतदान किया है।
  - ③ स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव के बाद किसी दल को सदस्यता ग्रहण कर ले।
  - ④ मनोनीत सदस्य के द्वारा 6 महीने के बाद कोई दल joining कर लिया गया है।
- इस कानून के माफ़े व मुकामाब देना ही दुसरे है।



### नुकसान

① सदस्यों को वाक-अभिव्यक्ति स्वतंत्रता  
 अधिक हुई है।

② पार्टी द्वारा विपक्षीय कार्य को जारी  
 रखा है। इसके सदस्य अपनी इच्छानुसार  
 निर्णय नहीं ले पाते हैं।

### कार्य

① पार्टी अनुशासन को बढ़ाया है।

② 1985 से पहले को अपेक्षा कम-बहुत  
 काम हुआ है।

कार्य, शीका व मध्यमवर्ग में  
 हाल ही में दब-बदल देखे गए।

उत्ति: इस कानून के प्रावधानों को

पुनः समीक्षा होनी चाहिए।

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।

(Candidate must not  
 write on this margin)



4. राष्ट्रपति और राज्यपालों के अध्यादेश लागू करने की शक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या हैं? साथ ही अध्यादेश लागू करने की शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु संरक्षोपायों का उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)

What are the various issues around ordinance making power of President and Governors? Also discuss the safeguards which are in place to prevent misuse of ordinance making power. (150 words) 10

राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 व राज्यपाल  
अनुच्छेद 213 के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों  
में अध्यादेश जारी कर सकते हैं -

- 1) जब संसद सत्र न चल रहा हो।
- 2) जब ऐसी परिस्थितियाँ हो कि कानून बनाना ज़रूरी ठाना जा सकता हो।

→ 1 इसके माध्यम से संसद की कार्यवाही से बचने का प्रयास किया जाता है।

→ 2 किसी मुद्दे पर विपक्ष को राय का अभाव हो जाता है।

→ 3 संसदीय समितियों की भूमिका निष्पत्ती हो जाती है।



इसके लाभ

- ① असमान्य परिस्थितियों में देश की सुरक्षा व अखण्डता में शक है।
- ② शैक्षिक सेवा सम्पूर्ण रूप नहीं चलती।  
अतः इमारतों की प्रावधानों के लिए अति आवश्यक है।

बुद्धिप्रभाव

- ① महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष को आलोचना से बचने का प्रयास।
- ② शैक्षिक मूल्यों का ह्रास होता है।

संरक्षोपाय

- ① सरकार के अंदर इसे लोकसभा में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ② किन परिस्थितियों में यह लाभ तथा यह भी बताना आवश्यक होता है।

शहरी व ग्रामीणों द्वारा इस प्रावधान को आवश्यक परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।  
(Candidate must not write on this margin)



5. लोकपाल के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या हैं? क्या लोकपाल का पद सरकार और अन्य, जिनकी जाँच हेतु इसे आज़ापित किया गया है, से स्वतंत्र है? (150 शब्द) 10

What are the duties and powers of Lokpal? Is the office of the Lokpal independent of the government and others whom it is mandated to scrutinise? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जल पिनाको चंद्र चौप को भारत का पहला लोकपाल बताने का निर्णय किया था।

### कर्तव्य

- ① भ्रष्टाचार को रोकना।
- ② पारदर्शिता को बढ़ाना।
- ③ सरकार व प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना।
- ④ भ्रष्ट लोगो के विरुद्ध कार्रवाई करना।

### शक्तियाँ

- ① इसके दायरे में प्रधानमंत्री, मंत्रियों से लेकर ग्रुप A से D तक के सभी अधिकारी-कर्मचारी आँगे।
- ② जहाँ भी लोकपाल के मामलों में इसके अधिकार होंगे।



③ विशेष न्यायलयों के गठन के माध्यम से 6 महीने में केस को निपटारा होगा।

### स्वतंत्रता

① इसकी निष्पत्ति 6 सदस्यों की समिति द्वारा की जायेगी।

② सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह ही दायता ला सकता है।

③ वेतन-भत्ते व पेंशन संबंधित विषय पर शक्ति है।

अब: लोकपाल को पर्याप्त रूप से स्वतंत्रता दी गई है हालांकि सरकारी अधिकारियों को जांच करने से पहले सरकार को सकारित आवश्यक है।

लोकपाल को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए ताकि अधिकांश को दूर किया जा सके।

उम्मीदवार को इस  
होशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

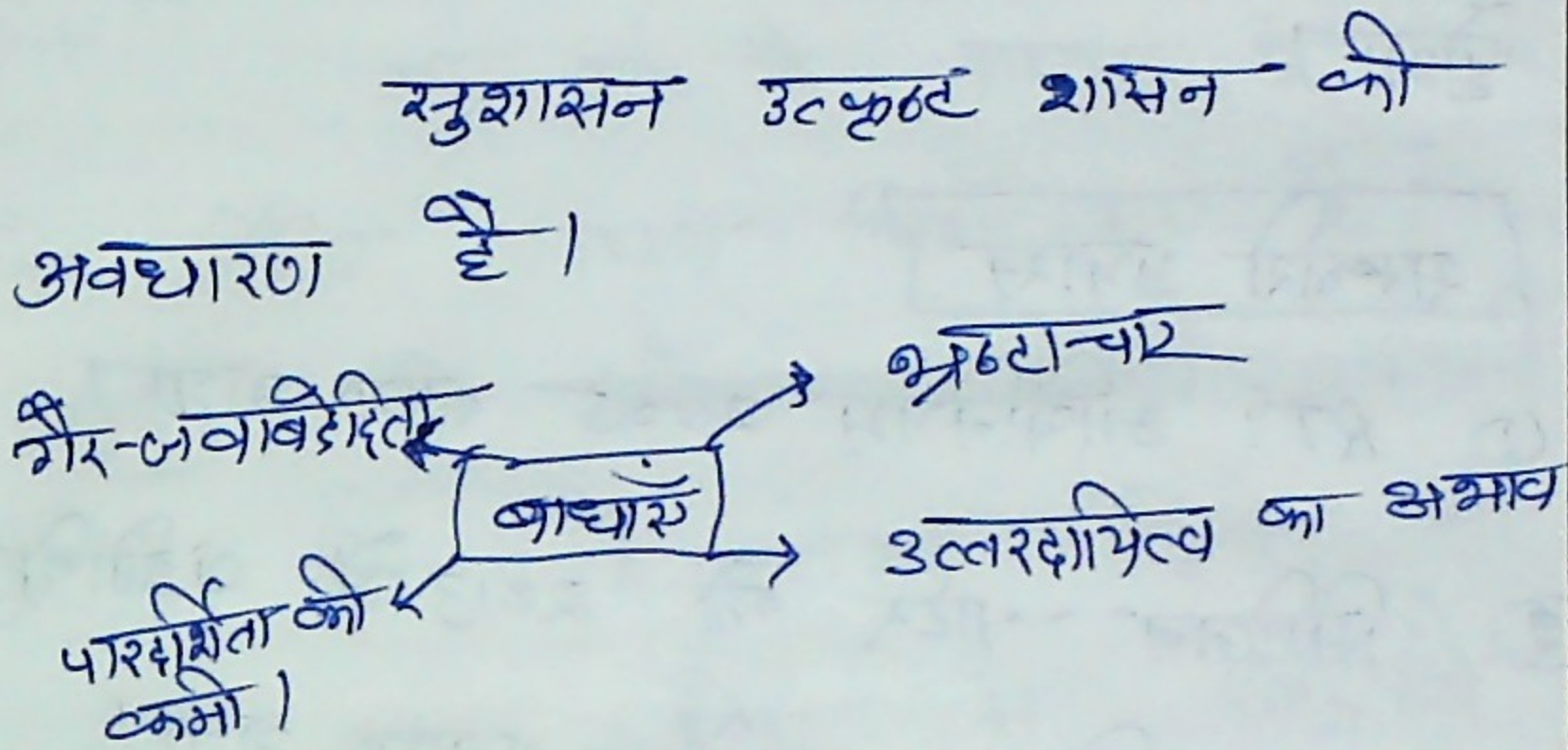


6. भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाओं को गिनाइये। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

Enumerate some of the key barriers to good governance in India. Taking cues from these barriers, discuss the necessary pre-conditions for good governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)



सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें

- ① जवाबदेहिता को बढ़ाना होगा।
- ② डिजिटल इंडिया के माध्यम से ई-गवर्नेंस को बढ़ाना होगा।
- ③ पारदर्शिता के लिए RTI, सेंट्रल एंटी कॉर्रप्शन ऑथोरिटी का लागू करना होगा।
- ④ मोशल आउट के माध्यम से जनता को सहभागी बनाना जा सकता है।



5) अधिकारियों को अप्रतिबद्धता  
मानसिकता में परिवर्तन लाना  
होगा।

### सरकारी प्रवास

1) RTI अधिनियम 2005 लागू हुआ।

2) सिटिजन चार्टर को 2013 में अंशोचित  
करके अधिकार पारदर्शी बनाया गया।

3) सेवोत्तम मॉडल जायू करने का  
प्रयास।

4) ODA के माध्यम से अधिकारियों को  
काम करने का प्रयास।

### सुशासन

1) सुशासन के लिए अब सरकार को  
अधिकारिक सूचकांक लाना के पास  
पहुँचानी पड़ेगी।

2) ई-शासन को बढ़ावा दिया जाये।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



7. अनुच्छेद 370 की संवैधानिक स्थिति क्या है? वर्तमान परिदृश्य में इससे संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

What is the Constitutional status of Article 370? Discuss issues and challenges related to it in the current scenario. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)

अनु० 370 के माध्यम से जम्मू  
के विशेष प्रावधान किए गए हैं।  
अनु० 370 की संवैधानिक स्थिति अस्थायी  
प्रकृति की है तथा किसी भी  
समय अन्य ठाकुर से राष्ट्रपति  
के द्वारा जम्मू-काश्मीर को विधायक  
की सहायता से इसे हटा  
जा सकता है।

Art-370 से संबंधित मुद्दे

- 1) इससे केंद्र के द्वारा GST, आरक्षण,  
DPSP जैसे विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों  
को लागू करने में समस्या आई  
है।
- 2) इससे जम्मू काश्मीर का अलग संविधान  
व संप्रदाय है जिसके कारण वह के



लोगों में असमाववाद को भावना  
आती है।

③ सहकारी संघवाद को भावना प्रभावी  
होती है।

पुनर्जागरण

① जम्मू कश्मीर में आंदोलन को  
समस्या को ~~कम~~ ~~करना~~ ~~है~~ ~~अभी~~

② इस प्रावधान को जब विधानसभा को  
सहमति से दया जा सकता है।

③ इस मुद्दे पर राज्य-केंद्र की पूर्ण  
सहमति ली नहीं बन पाई है।

केंद्र-राज्य संबंधों को अधिक  
मजबूत बनाने तथा जब के सुधारों

को देश को सुचारु धारा में लाने

के लिए इस प्रावधान को दृष्ट

देना उचित हो सकता है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



8. आपके अनुसार भारत में लोक सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख विकार कौन-से हैं? क्या लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) इनमें से कुछ विकारों का समाधान कर सकता है? (150 शब्द) 10

What do you think are some of the major ailments afflicting civil services in India? Can lateral entry in civil services address some of these ailments? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)

लोक सेवाओं सार्वजनिक सेवाओं  
को प्रदान करने व देश के सामाजिक  
आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका  
निभाती हैं।

लोक सेवाओं को प्रभावित करने वाले विकार

① अब विशेषज्ञता (स्कैट, पर्याप्तकरण) का युग  
भी है जबकि लोक सेवाओं सामान्य जन  
शर्यती हैं।

② राजनीतिक दूरतक्षेप।

③ निजी क्षेत्र के साथ शैथिल्यपूर्ण  
कार्य नहीं कर पाती।

④ आसवान समिति के अनुसार देश में  
1500 IAS को शोर आली हैं।



सरकार ने उच्च पदों पर  
लेखक संघों के माध्यम से अर्थी  
का निर्णय लिया है।

लेखक संघों से कुछ विकारों का समाधान

- ① विषय-विशेषकों को अर्थी किया जा  
सकता है।
- ② श्यावो पदों को समस्या का समाधान  
हो जाएगा।
- ③ निजी अनुभवों का फायदा स्थापित  
लोकसेवकों को भी होगा।

अब बदले युग के अनुसार  
सामान्य के साथ विशेषकों को भी  
आवश्यक है।

भा.प्र.सं. के मा.द. सरकारी नियोक्ताओं के  
माध्यम से 2024-25 तक 5 बिलियन 450  
अर्धचयवन्ध्या बनाना - यह है।  
लेखक संघों से फायदा हो रहा है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



9. एक कमजोर विपक्ष सत्ताधारी सरकार को तो खुश कर सकता है परंतु यह लोकतंत्र के हितों को नहीं साधता है। भारत में हालिया आम चुनावों के परिणाम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये।

(150 शब्द) 10

A weak opposition may make the government of the day happy but it does not serve the cause of democracy. Discuss the statement in light of the outcome of recent general elections in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

17वीं लोकसभा में सत्ता पक्ष  
को 320 से अधिक सीट मिली जिस  
कारण लोकसभा में विपक्ष की  
स्थिति कमजोर हो गई है।  
कमजोर विपक्ष सत्ताधारी सरकार के लिए  
अच्छा नहीं है

- 1) सरकारी नीतियों को आलोचना नहीं  
होगी।
- 2) सरकार को कमजोरियों को प्रकटी  
रूप से जनता के सामने नहीं आ  
पाएंगे।
- 3) सरकार अपने अनुसार अधिनियम  
बना सकती है।



कमजोर विपक्ष, लोकतंत्र के लिए खतरा

1) लोकतांत्रिक प्रक्रिया बरद-विवाद पर निर्भर करती है। विपक्ष कमजोर होने से सकारात्मक बदलाव नहीं हो पायेगी।

2) सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक श्रेय-धर्मों को हस्तक्षेप कर सकता है।

3) मुद्दों को विपक्ष के दृष्टिकोण से नहीं देखा जायेगा।

स्वस्थ व श्रेयनात्म लोकतंत्र

के लिए मजबूत विपक्ष का होना

आवश्यक है क्योंकि वह सत्ता

पक्ष को सकारात्मक आलोचना करता

है तथा मनमाने कानूनों से बचाता

(10)

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



10.

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के निर्धारण हेतु अनुपालित मानदंडों का उल्लेख कीजिये। उनके द्वारा किन मुद्दों का सामना किया जाता है? साथ ही इन मुद्दों के समाधान के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

State the criteria followed for the determination of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). What are the issues faced by them? Also mention the measures taken by the government to address these issues. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

भूवी वैद्यर समिति को अनुसूचकों  
पर 1983 में जनजातियों के मध्य कमजोर  
जातियों को विशेष रूप से कमजोर  
जनजातीय समूह (PVTG) घोषित किया गया।  
18 शर्तों व अठ्ठमान-निर्देशना  
में PVTGs का निवास है।

PVTG के निर्धारण हेतु मानदंड

- 1) जनसंख्या का स्थिर होना या बढ़ती हुई दर।
- 2) सामाजिक अलगाव।
- 3) वार्षिक रूप से पिछड़ापन।
- 4) विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य।
- 5) अज्ञानता व निर्धनता।



PVTG द्वारा सामना किए गए बड़े मुद्दे

- 1) पर्यटकों व बाहरी लोगों द्वारा शोषण  
eg - USA नागरिक का सेंटनलीन दीप पर  
क्रमण।
- 2) वनों व अरुण उपजाऊ बनने  
के कारण खाने की समस्या।
- 3) संक्रमण रोगों से प्रभावित।
- 4) अशिक्षा, अनुशासना की स्थिति।
- 5) प्रशासन का असंबुद्ध नागरिक

सरकारी प्रयास

- 1) जनजातीय मंगलप ने PVTG के विकास  
के लिए विशिष्ट योजना चलाई है।
- 2) इन क्षेत्रों में Restricted Area Scheme  
लागू किया गया है।
- 3) अनुमान सरकार द्वारा PVTG के लिए  
व्यक्तिगत विकास योजना बनाया है।

PVTG की विशिष्ट संरचना को  
संरक्षित करते हुए उनके विकास के  
प्रयास किए जाने चाहिए।



11.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप, 2019 भारत के शिक्षा क्षेत्र को एक नया आकार दे सकता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Draft National Education Policy, 2019 can give a new shape to India's education sector. Critically examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में के. नरसुरीश्वरन समिति

द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।

इससे पहले देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चर्चा हुआ

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों?

1) अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन आया है।

2) बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन अब अनुसंधान की अधिक आवश्यकता है।





drishti



3) पूर्व नीतियों से <sup>लगातार</sup> आउटकम बेहतर नही आर है। सु- प्रथम N40 को

ASER रिपोर्ट के अनुसार 5वीं कक्षा

का बच्चा लिखने का काम नही पढ़ पाता है।

नई शिक्षा नीति शिक्ष क्षेत्र को नया आकार दे सकती है

1) इसमें तीन वर्ष से छोटे बच्चों को शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। इससे शिक्षा में नया आयाम बूड़ेगा।

2) इसने RTE 2009 को 12वीं कक्षा तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। अब 8वीं से 12वीं कक्षा भी अधिकांश के लिए में आया है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



3) अनुसंधानों पर अधिक बल दिया गया है।

4) शिक्षण-प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित।

आलोचना

1) इनके शिक्षकों के खाली पदों पर विशेष ध्यान नहीं है।

2) निजी शिक्षा के प्राथमिकता को रोकने का विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

3) विलीयन के लिए स्पर्धा का अभाव है।

आवश्यक है कि प्रायः को नीति का रूप देने से पहले व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से किया जाए।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)



12. "सामाजिक अंकेक्षण परिकल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में सहायता प्रदान करता है।" इस कथन का परीक्षण कीजिये और भारत में सामाजिक अंकेक्षण को प्रणालीबद्ध करने में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

"Social audit helps to narrow gaps between vision and reality." Examine the statement and also discuss the impediments in institutionalization of social audit in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

द्वारा सभी सरकारी योजनाओं में  
सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य  
किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण सरकारी  
कार्यों में जनता को सहभागिता  
को सुनिश्चित करता है।

परिकल्पना व वास्तविकता में अंतर  
को कम करने में सहायता करे।

1) अनियमितताओं को कम करने  
सह्ये लाभार्थी तक ही लाभ  
पहुंच पाता है।



२) मानकों के अनुसार ही  
सेवाएँ मिल पाती हैं।

३) अत्याचार को समय पर  
उठाकर काम अधिक उत्तरदायित्व  
सुनिश्चित करता है।

४) जनता को सहभागी बनने से  
विलोप अनिष्टमित्रताएँ कम हो  
जाती हैं।

५) समय बहता सुनिश्चित होता है।  
उपरोक्त प्रावधानों के कारण  
परिष्कल्पना व वास्तविकता के बीच  
को खाई कम हो जाती है।  
इसके बावजूद भी सामाजिक  
अकेलापन अभी वास्तविकता नहीं बन

उम्मीदवार को इस  
हार्शिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)



पा रहा है। इसे प्रणालीगत करने  
में निम्नलिखित बाधाएँ का इच्छ  
है -

- 1) कानूनी समर्थन का अभाव।
- 2) जनता में जागरूकता का अभाव।
- 3) जनता में अकेलापन के विरुद्ध  
पर्याप्त कोशिश का न होना।
- 4) अधिकारियों को कर्मचारी  
मानसिद्धता।

अतः जब आवश्यकता है कि  
मेधाव्य को तरह अन्य बाधाओं  
समाप्ति अकेलापन को कानूनी  
समर्थन प्रदान करें।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



13. 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के समक्ष आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों को हल करने में नाकाम रहा है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

73<sup>rd</sup> Amendment Act has failed to address the systemic challenges faced by Panchayati Raj Institutions (PRIs). Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

73वें संशोधन अधिनियम 1973 के  
द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को  
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

विशेषताएँ

- 1) तीन स्तरों (ब्लॉक, ग्राम, जिला) पर  
सैक्यनात्मक गठन किया गया।
- 2) निश्चित चुनावों का प्रावधान  
किया गया।
- 3) 23 विषयों को प्रदान किया गया।
- 4) महिलाओं व अनुसूचित जाति-जनजातियों  
को मंचावृत्त करने का प्रयास किया  
गया।



प्रणालीगत चुनौतियाँ

1) रेगुलर वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वित्त का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।

2) ग्राम सभा की नियमित बैठकें आयोजित नहीं होती हैं।

3) निर्वाचित महिलाओं के प्रति हस्तक्षेप करते हैं।

4) चुनावों में अपारदर्शिता व धनबल का समाधान नहीं हो पाया है।

+ve

1) इसने 83% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है लेकिन अब PRTS में महिला प्रतिनिधियों का शेड्यूल औसत 44% है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)



2) लोकतर में लोगों को सहभागिता को बढ़ाया तथा लोकतांत्रिक सूत्रों से अवगत कराया।

उम्मीदवार को इस  
हारा में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

3) निपामित रूप से चुनावों का संचालन किया जाता है।

4) ई-शासन के माध्यम से पंचायतों का डिजिटलीकरण हो रहा है (आरोग्य के द्वारा 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के नेटवर्क से जोड़ना)

सभी प्राथमिक समसमयों को समाप्त नहीं हो सके हैं। अतः 18वें संशोधन को समीक्षा करके इसे अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है।



14. किसी लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और जवाबदेह न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षोपाय है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

An independent and accountable judiciary is the best safeguard of citizens' rights in a democracy. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

संविधान में अनुच्छेद 124 से  
147 के मध्य न्यायपालिका की  
स्वतंत्रता व जवाबदेहिता के बारे  
में उपबंध दिए गए हैं।

न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है?

- 1) न्यायाधीशों को नियुक्ति केन्द्र की सीमित भूमिका है।
- 2) महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा ही हटारा जा सकते हैं।
- 3) वेतन-भत्ते व पेंशन संबंधी विषय पर शक्ति होते हैं।

न्यायपालिका जवाबदेह कैसे?

- 1) संविधान के अनुच्छेद-32 के अनुसार



आधिकारों के मौलिक अधिकारों के  
रक्षण को सुनिश्चित करने के लिए

उम्मीदवार को इस  
हार्शिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

2) अधिकारों के उल्लंघन को  
स्थिति में लोगों को सुनिश्चित करने  
के लिए सुनिश्चित करना मना नहीं कर  
सकती।

स्वतंत्र व जवाबदेह सुनिश्चित नागरिकों  
के अधिकारों का सर्वोत्तम उपाय

1) यदि सुनिश्चित स्वतंत्र है तो  
वह राज्य के हस्तक्षेप के बिना  
कार्य करेगी।

2) नागरिक अधिकारों के उल्लंघन  
को स्थिति में स्वतंत्र संवैधानिक माध्यम  
से लोगों के अधिकारों के प्रति  
जवाबदेह रहेगी।



3) पीड़ितों को मुआवजा दिलायगी (सु-इन्सायुरेंस रीप पीडिता को) तथा दोषी को जल्दी सजा सुनिश्चित करेगी।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)

4) दबाव में काम करने वाली न्यायपालिका  
सत्ता पक्ष के अडसर कार्य करती  
है तथा वह नागरिकों के अधिकारों  
के प्रति कम उत्तरदायी रह जाती  
है।

लोकतंत्र में स्वतंत्र व पराकीर्ण  
न्यायपालिका के माध्यम से लोगों  
के अधिकारों के साथ साथ सद्भाव  
सेवा तथा शक्ति पुनर्करण सिद्धांत  
को भी रखा देती है।



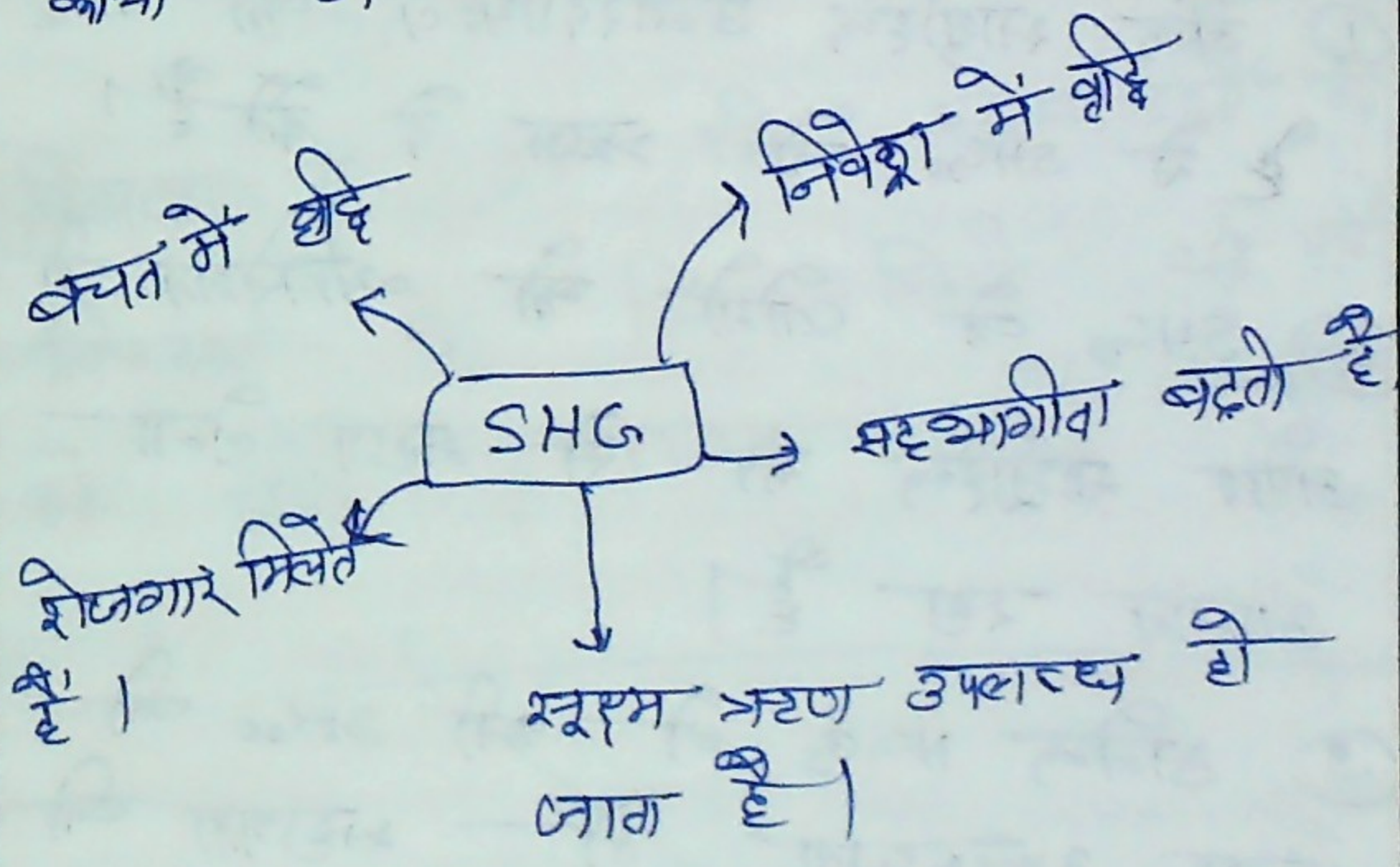
15. स्वयं सहायता समूह गरीबों को सूक्ष्म वित्त सेवाओं के वितरण के लिये सबसे प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Self-Help Groups have emerged as the most effective mechanism for delivery of microfinance services to the poor. Critically examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हारा में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

स्वयं सहायता समूह प्रायः शकसमय  
आर्थिक स्थिति वाले निरधन लोगों  
का समूह होता है जो स्वेच्छा  
से बचत व निवेश करके सूक्ष्म  
कार्य में संलग्न रहते हैं।



SHGs के कार्य

1) महिलाओं को कार्य करने की प्रेरणा



का विकास हुआ है।

(2) निर्धनों को समय पर ऋण की उपलब्धता।

(3) सहभागिता को बढ़ावा मिला है।

SACs शरीरों को सूक्ष्म वित्त सेवाओं के विवरण के लिए प्रभावी तंत्र

(+ve)

(1) बैंक सामुहिक उत्तरदायित्व को बढ़ा है से SACs को ऋण दे रहे हैं।

(2) SACs के लोगों को व्यक्तिगत की अपेक्षा सामुहिक रूप से ऋण लेना आसान रहा है।

(3) अनेक NGOs ने भी SACs को ऋण उपलब्धता में सहायता की है।

(4) SAC-बैंक विप्रेत प्रोग्राम ने भी वित्त में सहायता को है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)



(-10)

① इस ऋण का समूह के प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से प्रयोग कर के है।

② समय पर ऋण नहीं मिलता।

③ परमाणु ऋण की उपलब्धता नहीं हो पाती।

सुझाव

SMGS को सूक्ष्म वित्त सेवाओं के विवरण में आ रहे समूहों के निवारण के लिए किसी बड पार्टी से स्वीकार कराया जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)



16. भारत जैसे देश में आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता के लिये संतुलित क्षेत्रीय विकास अति आवश्यक है। 'आकांक्षी जिलों के परिवर्तन' कार्यक्रम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Balanced regional development is quite essential for economic progress and political stability in a country like India. Discuss the statement in light of 'Transformation of Aspirational Districts' programme. (250 words) 15

सरकार ने समावेशी विकास  
को सुनिश्चित करने के लिए देश  
के 115 जिलों को आकांक्षी जिलों  
के परिवर्तन कार्यक्रम में शामिल  
किया है।

आकशकॉम की रिपोर्ट के अनुसार  
भारत के 1% लोगों के पास अरब  
की 58% संपत्ति है। ~~अरब~~ अरब  
के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों  
का देश के निर्यात में 50% से भी  
ज्यादा योगदान है। अतः भारत में  
संतुलित क्षेत्रीय विकास नहीं है।



आर्थिक प्रगति व राजनीतिक स्थिरता  
के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास आवश्यक  
क्यों ?

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

① असंतुलित क्षेत्रीय विकास पिछड़े राज्यों  
में असंतोष की भावना पैदा  
करता है। जिससे जनसत्तावाद, उग्रवाद  
तथा श्रेष्ठवाद प्रवृत्तियों को बढ़ावा  
मिलता है जिससे राजनीतिक स्थिरता  
प्रभावित होती है।

② आर्थिक प्रगति लोगों के उपभोग  
पर भी निर्भर करती है। विश्व बैंक  
के अनुसार अमीर लोग उपभोग पर  
कम पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति  
रखते हैं। यदि संतुलित विकास नहीं  
होगा तो इससे देश का आर्थिक



विकास भी प्रभावित होगा।

3) विदर्भ, गोरखालैंड जैसे पिछड़े क्षेत्र  
शासकीय स्थिरता को चुनौती दे  
सकते हैं।

आजोड़ी जिलों के परिवर्तन कार्यक्रम का  
उद्देश्य पिछले जिलों में शिक्षा, कौशल,  
स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि  
करके दीर्घकालिक रूप से देश  
को आर्थिक प्रगति व शासकीय  
स्थिरता को ही सुनिश्चित करना  
है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



17. शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को आगे बढ़ाने का एक संभावित मंच है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a potential platform to advance India's 'Connect Central Asia' policy. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

हाल ही में भारत को शंघाई  
सहयोग संगठन (SCO) की पूर्ण सदस्यता

प्राप्त हुई।



→ SCO के  
सदस्य

भारत ने मध्य एशिया के पाँच  
देशों ( अफ़ग़ानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़बेकिस्तान,  
किर्गिस्तान, — ) से सम्बन्धों को बढ़ावा  
 देने के लिए 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया'  
 नीति को लागू किया था।  
 मध्य एशिया के इन पाँच  
 देशों में से चार देश SCO



के भी सदस्य हैं। अतः SCO के माध्यम से निश्चित रूप से भारत अपनी 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को बढ़ाना चाहेगा है।

SCO, कनेक्ट सेंट्रल एशिया के कदम का संभावित मंच कैसे ?

- 1) मध्य एशिया के चार देश SCO में भी शामिल हैं।
- 2) मध्य एशिया में चीन-रूस व पाकिस्तान का भी प्रभाव है। अतः इन देशों के साथ मिलकर कार्य करने से मध्य एशिया से और अधिक सम्बन्ध बचेंगे।
- 3) SCO के माध्यम से सैन्य आश्वास

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)



(RATS) में भी सहभागीता बढ़ेगी।

4) SCO के कार्रवाई में मध्य एशिया के देशों के शासकों से प्रतिवर्ष मिलने का मौका मिलेगा।

5) सरकार ने INSTC, अहमदाबाद समझौते के माध्यम से भी एशियन सेंट्रल एशिया नीति को बढ़ाने का प्रयास किया है।

सुझाव

1) ऊर्जा सुरक्षा के लिए SCO व सेंट्रल एशिया नीति के अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। Eg- तापी परियोजना।

2) रूस-चीन के साथ सम्बंधों को बेहतर करने के लिए भी SCO अपना योगदान देना चाहिए।

अतः भारत को SCO के माध्यम से दोनों दिशाओं को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)





drishti



18. दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ाने में सार्क की विफलता ने क्षेत्रीय देशों को बिमस्टेक के रूप में एक व्यावहारिक विकल्प तलाशने हेतु प्रेरित किया है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

The failure of SAARC to nurture cooperation in South Asia has pushed regional players to explore BIMSTEC as a viable alternative. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

वर्ष 2016 के पठानकोट हमले के बाद सार्क को बँकनी बचाव की शक्ति का दिया गया था।

इसकी स्थापना के बाद से भी प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका।

सार्क की विफलता के कारण

- 1) पाकिस्तान द्वारा क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ाने के कारण।
- 2) सार्क सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों के कारण सहमति नहीं बन पाती।
- 3) मोटर विकल्प शक्ति पर पाकिस्तान का अडिग सख।



4) सीमा विवादों व जल-सीमा विवादों ने भी इसकी विफलता को बढ़ाया है।

सार्क की विफलता के बाद से विमसैक एक अवधारण विफल के रूप में उभरा है -

1) अफगानिस्तान व पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के सदस्य विमसैक के भी सदस्य है।

2) यह दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया में भी सहयोग बढ़ाने में भूमिका निभाएगा।

3) विमसैक के सदस्यों ने मध्य द्विपक्षीय विवाद का है तथा सहयोग के अनेक क्षेत्र है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)



## भारत की शान्ति

1) सरकार ने पड़ोसी देशों में  
विद्रोहों के सड़कों को बुलाकर  
सेठन को मजबूत करने का  
प्रयास किया है।

2) शांति की बातों को भी  
पुनः पाव करना चाहिए परंतु  
विद्रोहों के माध्यम से विशेष  
रुग्णों सहयोग पर अधिक  
ध्यान दिया जाय।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



19. भारत के लिये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) का क्या महत्त्व है? विशेष रूप से चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये इसके निहितार्थ का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

What is the significance of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) for India? Examine its implications for the Indian economy especially in the context of free trade agreement with China. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

### क्षेत्रीय आर्थिक विकास समझौता (RCEP)

आसियान के 10 देशों तथा भारत, चीन, जापान, द. कोरिया, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार

समझौता है।

- RCEP का महत्त्व
- ① यह WTO के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन होगा।
  - ② इन देशों के मध्य सेवाओं व वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि आएगा।
  - ③ भारत की रणवट ईस्ट पॉलिसी को फायदा होगा।
  - ④ निवेश में वृद्धि होगी।



भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए RCEP के निहितार्थ :-

1) इसे उद्योगों, सेवाओं, पेटेंटों तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है।

2) कुशल लोगों के मुक्त आवागमन को बढ़ावा मिलेगा जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होगी।

3) भारतीय सेवाओं के लिए आसियान देशों के बाजार में वृद्धि होगी।

चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते

के संबंध में RCEP का भारत के लिए निहितार्थ

1) चीन के साथ भारत का अर्थव्यवस्था व्यापारिक घाटा है (40 b \$)। RCEP के माध्यम से चीनी वस्तुओं की

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)



भारतीय बाजारों में और अधिक  
पहुंच बढ़ जायेगी। अतः भारतीय  
उद्योग प्रभावित होंगे व व्यापारिक  
घाटा भी बढ़ेगा।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

सुझाव

- 1) चीन के साथ 80% तक वस्तुओं  
के लेन-देन मुक्त व्यापार सम्झौता कर  
जा सकता है।
- 2) भारत को अपनी वस्तुओं के निर्यात  
भी बाजार पहुंच बढ़ाने चाहिए।
- 3) भारत को चीन में अधिक आर्थिक  
गलतियों को ठीक करने चाहिए।  
RCEP में यदि भारत को  
पक्षों पर ध्यान दिया जाता है तो  
यह निश्चित रूप से लाभदायी  
साबित हो सकता है।



20. निरंतर हठधर्मिता दिखाते चीन के साथ संबंधों को बनाए रखना भारतीय विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में उभरा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Dealing with an increasingly assertive China has emerged as one of the principal challenges of Indian foreign policy. Discuss in the context of China's growing influence in South Asian region. (250 words) 15

डोकलाम विवाद के समय  
भारत-चीन के मध्य संबंधों में  
एकराइट पैदा हुई।

चीन की निरंतर हठधर्मिता

- 1) चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को अपना भू-भाग बता रहा है।
- 2) 'स्ट्रिंग आउट पॉलिसी' नीति के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है।
- 3) 'भारत-चीन आर्थिक गलियारा' के द्वारा भारत की संप्रभुता का उल्लेखन किया।
- 4) मसूदा अध्याय को लेकर UNSC-1267 प्रस्ताव पर बाधा पहुंचायी थी।



इस प्रकार चीन के साथ अल्प  
नीति के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में  
से एक है।

भारतीय विदेश नीति के समक्ष अन्य

चुनौतियाँ

- 1) USA व रूस के मध्य संबंधों में  
संतुलन बनाना।
- 2) ईरान - USA व चीन के मध्य बढ़ती  
तकराव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति  
बनाना रखना।
- 3) हिन्द महासागर में अपने हितों को  
सुरक्षित रखना।

दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव

- 1) चीन के द्वारा बंगलादेश तथा श्रीलंका  
में बड़े पैमाने पर निवेश किया  
जा रहा है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



2) नेपाल के साथ संचार व्यवस्था व  
रैलवे निवेश समझौते ।

3) भारत व भूटान को छोड़कर दक्षिण  
एशिया के सभी देश OBR में  
शामिल हो गए हैं ।

सुझाव

1) चीन भारत का पड़ोसी है अतः

भारत-चीन को मिलकर शक्ति सदी  
को रूसिया को सबो बनाने का

प्रयास करना चाहिए ।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।  
(Candidate must not  
write on this margin)